## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### ASEAN—Based Shipping Conference

*503. SHRI C. K. CHANDRAPPAN. Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether ASEAN-based shipping conference would come up soon;

(b) how far this would help to break the monopoly of Far East Freight Conference; and

(c) broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M. TRIVEDI): (a) The Government have received no definite information about any such proposal

(b) and (c) Do not arise

### Visit by West German Business Delegation

*505. SHRI RAGHUNANDAN LAL BHATIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether West German business delegation had visited India in March, 1976; and

(b) if so, the outcome thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS). (a) Yes, Sir.

(b) The visit provided both sides with an opportunity to exchange views on various economic matters of mutual interest thereby promoting better understanding for the development of economic and commercial relations between the two countries.

### गंगा पर पुल

*510 श्री शंकर दयाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पटना में गंगा पर बनाये जा रहे पुल के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितने धन का आवंटन किया है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) पुल निर्माण की प्रगति क्या है और उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है , और

(घ) यह कब तक पूरा हो जायेगा ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)

(क) से (घ) : पटना से निर्माणाधीन गंगा पुल राज्य सड़क पर पड़ता है और इस लिए इस परियोजना से बिहार सरकार मुख्यत: संबंधित है । परन्तु इस पुल के निर्माण में राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार चौथी योजना अवधि में व्यय का 50% उसी योजना में गैर योजना ऋण देने के लिए सहमत हो गई बशर्ते कि वह राशि 4 50 करोड रू० से अधिक न हो, शेष सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार को अपने साधनों से पूरी करनी होगी । 4 50 करोड रू० की यह राशि चौथी योजना अवधि में राज्य सरकार को यथाविधि दे दी गई ।

उपरोक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता को जारी रखने के लिए पांचवी योजना में कोई व्यवस्था नहीं है । अत: अब पुल का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा अपनी पांचवी योजना

के आंकड़ों से किया जा रहा है जिसमें प्रक्षणगत पुल के लिए 21.55 करोड़ रू० की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा परियोजना संस्थापन के लिए 1.20 करोड़ रू० की व्यवस्था भी है।

राज्य सरकार द्वारा अब तक किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

| | (रूपये करोड़ो में) |
|---|---|
| चौथी योजना | |
| 1969–74 | 11.01 ( इसमें से 4.50 करोड़ रू० की केन्द्रीय ऋण सहायता है) |
| 1974–75 | 5.43 जमा 0.24 करोड़ (परियोजना संस्थापन) |
| 1975–76 | 8.26 जमा 0.24 करोड़ |

1976–77 के लिए योजना आयोग पुल परियोजना के लिए 7.0 करोड़ रू० की व्यवस्था के लिए सहमत हो गया है जिसमें, जैसा कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया था, 0.26 करोड़ रू० परियोजना संस्थापन के लिए शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारो (मैसर्स गैम्मोन्स इंडिया लि०) के साथ किये करार के अनुसार पुल जून 1978 तक पूरा किया किया जाना है।

**Malangtoli Iron Ore Project Report**

*513. SHRI P. GANGADEB: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Malangtoli Iron Ore Project report is near completion; and

(b) whether top priority is proposed to be given for the report to reach the Ministry by the end of 1976?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI CHANDRAJIT YADAV): (a) and (b). Field investigations being conducted by the National Mineral Development Corporation Limited at Malangtoli are expected to be completed by the end of 1976. Preparation of a Project Report will take about six months after the results of these investigations become available.

**Development of Chettua as a Major Port**

*516. SHRI VARKEY GEORGE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Government have got any scheme to develop Chettua as a major port in Kerala;

(b) if so, the total cost involved in this scheme; and

(c) the time by which it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M. TRIVEDI): (a) No, Sir.

(b) and (c). Does not arise.

**Alleged Poaching into Areas covered by Indian Shipping Lines**

*517. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY:

SHRI BHOGENDRA JHA:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of poaching into the areas normally covered by Indian Shipping Lines